

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खानपुर जिला झालावाड़
(मीटासीन अधिकारी - श्री प्रमोदकुमार सिंघव आर.ए.एस.)

मिसल नं० 5 2 4/प्रार्थना-पत्र/2019

{मि० नं० 753/दावा/17 दायरा 17/07/17}

उनवान

1. घनश्याम पुत्र रामनाथ जाति गुर्जर निवासी भीलखेडा तह० खानपुर
 2. मोतीलाल पुत्र रामनाथ जाति गुर्जर निवासी भीलखेडा तह० खानपुर
 3. रामरतन पुत्र रामनाथ जाति गुर्जर निवासी भीलखेडा तह० खानपुर
 4. गोपाल पुत्र रामनाथ जाति गुर्जर निवासी भीलखेडा तह० खानपुर
 5. जयपाल पुत्र रामनाथ जाति गुर्जर निवासी भीलखेडा तह० खानपुर
 6. कस्तूरीबाई पुत्री रामनाथ जाति गुर्जर निवासी भीलखेडा तह० खानपुर
 7. बृला पुत्र किशना जाति गुर्जर निवासी भीलखेडा तह० खानपुर
 8. गोरधीलाल पुत्र किशना जाति गुर्जर निवासी भीलखेडा तह० खानपुर
 9. भूमली पुत्री किशना जाति गुर्जर निवासी भीलखेडा तह० खानपुर
 10. बलराम पुत्र विरवा जाति गुर्जर निवासी भीलखेडा तह० खानपुर
 11. तुलस्या पुत्र भैरुलाल जाति गुर्जर निवासी भीलखेडा तह० खानपुर
 12. कजोड पुत्र भैरुलाल जाति गुर्जर निवासी भीलखेडा तह० खानपुर
 13. पानाबाई देवा भैरुलाल जाति गुर्जर निवासी भीलखेडा तह० खानपुर
- वादी/अप्रार्थी

बनाम्

1. द्वारकालाल पुत्र लटूर जाति गुर्जर निवासी भीलखेडा तह० खानपुर
2. कंचनबाई पुत्री लटूर जाति गुर्जर निवासी भीलखेडा तह० खानपुर
3. राजीबाई पुत्री श्रीलाल जाति गुर्जर निवासी भीलखेडा तह० खानपुर
4. सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया शाखा खानपुर
5. राजस्थान सरकार जय्ये तहसीलदार साहब तहसील खानपुर
6. भू अवाप्ति अधिकारी परवन सिंघाई परियोजना झालावाड़

- प्रार्थी/प्रतिवादीगण

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 209 आर.टी.एक्ट 1955 एवं प्रार्थना-पत्र
अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जा०दी०

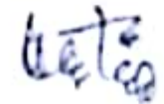
उपस्थित:- श्री रमेशकुमार विजय एडवोकेट - प्रार्थी/प्रतिवादी नं० 1, 2, 3
श्री हितेश राठौर एडवोकेट - अप्रार्थी/वादी

निर्णय

दिनांक 23/10/2019

प्रार्थना-पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं। प्रार्थी/प्रतिवादीगण 1, 2
ने दिनांक 22.02.2018 को जय्ये अधिवक्ता एक प्रार्थना-पत्र आदेश 7 नियम 11 सिविल

(1)


उपखण्ड अधिकारी
खानपुर जिला झालावाड़
(राजस्थान)

प्रक्रिया संहिता 1908 के अन्तर्गत इस आशय का प्रस्तुत किया है कि प्रस्तुत वाद वादीगण ने मौखिक वैचान करना प्रदर्शित कर पेश किया है और खातेदारी अधिकारों की घोषणा चाही है। प्रार्थी अन्य आधारों सहित निम्न आधारों पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हैं:-

1. यह कि प्रचलित राजस्व विधि में मौखिक वैचान से किसी भी प्रकार के अधिकार उत्पन्न नहीं होते हैं तथा राजस्व विधि के अनुसार वाद वर्जित है।
2. यह कि वादीगण ने कब्जा मुखालफाना के आधार पर भी खातेदारी की घोषणा माननीय न्यायालय से चाही है, जो प्रचलित राजस्व विधि अनुसार वर्जित है।
3. यह कि वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद विधि के प्रावधानों के विपरीत पेश किये जाने से स्वतः खारिज होने को मोहताज है।
4. यह कि वादीगण ने महज प्रार्थीगण के भूमि के अवाप्ति मुआवजों को रूकवाने की वदनियत से प्रार्थना पत्र पेश किया है, जबकि वादीगण सहखातेदार होने के बावजूद मुआवजा प्राप्त कर चुके हैं।

अतः प्रार्थना-पत्र पेश कर अर्ज है कि वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद विधि द्वारा वर्जित होने से खारिज फरमाने की कृपा करें।

प्रार्थना-पत्र की नकल अधिवक्ता अप्रार्थी/वादी को दिलायी गयी, जिन्होंने प्रार्थना-पत्र का जवाब इस प्रकार पेश किया कि हमने वैचान के आधार पर ही उक्त वाद को पेश किया है। वादी ने अपने परिवारजन होने के नाते उक्त वैचान को तस्दीक किया है। वादी व प्रतिवादीगण आपस में परिवारजन ही हैं और उक्त आराजी पर लगभग 60 वर्षों से वादीगण व उनके पूर्वजों का कब्जा चला आ रहा है। लेकिन प्रतिवादीगण ने आज दिन तक भी कोई उजर दावा नहीं किया है। वादीगण ने कई बार प्रतिवादीगण से रजिस्ट्री वावत् कहा लेकिन प्रतिवादीगण हमेशा टालमटोल करता रहा है। प्रतिवादीगण पिछले 45 वर्षों अर्थात् वैचान के कुछ समय वाद ही ग्राम भीलखेड़ा छोड़कर कहीं अन्य स्थान पर रहने लग गया है। इन्होंने यह स्पष्ट नहीं किया है कि वाद विधि विरुद्ध कैसे है। हमारा वाद खातेदारी की घोषणा का है जो गवाहान व सबूतों को लिये बगैर निस्तारण किया जाना न्यायोचित नहीं है। इस स्टेज पर प्रकरण खारिज किया जाना गलत है। इनका प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे। वकुलाय फरीकेन की सहमति से प्रार्थना-पत्र पर वहस उभय पक्ष सुनी गयी।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/प्रतिवादी ने अपनी वहस में प्रार्थना-पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये प्रकट किया कि वादीगण मौखिक वैचान एवं कब्जा मुखालफाना के आधार पर अपना वाद लेकर आये हैं। प्रचलित राजस्व विधि में मौखिक वैचान एवं कब्जा मुखालफाना के आधार पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा किया जाना वर्जित है। वादीगण, वाद में वर्णित आराजी में सह खातेदार हैं, जिन्होंने अपनी मुआवजा राशि तो प्राप्त कर ली है तथा प्रार्थी/प्रतिवादीगण की मुआवजा राशि को रूकवाने की वदनियती से यह वाद पेश किया है, जो विधि के प्रावधानों के विपरीत है। अतः हमारा प्रार्थना-पत्र स्वीकार कर इनका वाद खारिज फरमाया जावे।

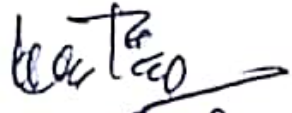
विद्वान अधिवक्ता अपार्थी/पार्थी ने अपनी बहस में जवाब प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये प्रकट किया कि हम वैचान एवं कब्जा मुखालफाना के आधार पर ही वाद लेकर आये हैं। वादीगण ने वादग्रस्त आराजी में से खातेदार दूमा ने अपना 1/2 हिस्सा आज से 60 वर्ष पूर्व वादीगण के दादा कालूलाल को वैचान कर दिया था, तब से ही हमारे परिवार का निर्विन्न रूप से ऐलानिया कब्जा इस आराजी पर चला आ रहा है। हमारा वाद खातेदारी अधिकारों की घोषणा का है, जिसे साक्ष्य व समूत लिये जाने के बाद ही निर्णित किया जाना न्यायोचित है। इस स्टेज पर दावा खारिज किया अन्याय पूर्ण होगा। अतः इनका प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

हमने पत्रावली का अक्षोभांत अध्ययन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। वादीगण ने ग्राम भीलखेड़ा की खतीनी सं० 41 की 5 किता शकवा 4408 बीघा में से प्रति० 1 लगा० 3 का नाम खाते से खारिज किया जाकर वादीगण को सम्पाम से खातेदार टीनेंट घोषित किये जाने का यह वाद इस आधार पर पेश किया है कि 60 वर्ष पूर्व खातेदार दूमा ने उसके 1/2 हिस्से का वैचान वादीगण के दादा कालूलाल को करके कब्जा आराजी सम्पला दिया था। वादग्रस्त आराजी पर ऐलानिया बिना किसी वाधा के विगत 60 वर्षों से भी अधिक समय से कब्जा काश्त होने के कारण वादीगण कब्जा मुखालफाना के सिद्धान्त के आधार पर खातेदार टीनेंट घोषित होने योग्य हैं। वादीगण ने अपने वाद के साथ कोई वैचाननामा पेश नहीं किया है। वादीगण आराजी का मौखिक वैचान होना कहते हैं और मौखिक वैचान के आधार पर वादीगण खातेदारी अधिकारों की घोषणा कराने के अधिकारी नहीं हैं। वहीं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अन्तर्गत कब्जा मुखालफाना के आधार पर खातेदारी अधिकार दिये जाने के का भी कोई प्राक्वान नहीं हैं। अधिवक्ता प्रार्थी/प्रतिवादी ने अपने प्रार्थना-पत्र के समर्पण में आर.आर.टी. 2017(2) पेज 883 लूनियावास गृह निर्माण सहकारी समिति लि० बनाम् स्टेट ऑफ राजस्थान, आर.आर.टी. 2016(1) पेज 723 रामप्रताप बनाम् कमलाबाई, आर.आर.टी. 2018(1) पेज 175 छीतर एवं अन्य बनाम् श्रीमती भवंशीदेवी एवं अन्य की नजीरें भी पेश की जिनका अवलोकन किया जाकर शामिल पत्रावली की गयी।

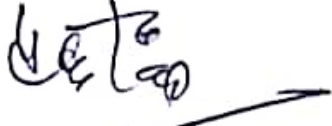
वादीगण ने अपने वाद की मद नं० 13 में अंकित किया है कि " यह कि वाद कारण दिनांक 01.07.2017 को उत्पन्न हुआ जब प्रतिवादी नं० 1 लगायत 3 से चलकर खाते से नाम खारिज करवाने की कहने पर उन्होंने मना कर दिया तथा वाला वाला ही मुआवजा राशि लेने की तैयारी करने लग गये।" यहां जब आराजी का वैचान होना साबित नहीं है और कब्जा मुखालफाना के आधार पर वादग्रस्त आराजी में वादीगण को कोई अधिकार सृजित नहीं होते तो दिनांक 01.07.2017 को वाद कारण उत्पन्न होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है और जब वादीगण को वाद कारण ही उत्पन्न नहीं हुआ है तो विधि अनुसार वादी का वाद चलने योग्य ही नहीं है। यहां वादग्रस्त में प्रतिवादीगण सहखातेदार दर्ज रेकार्ड हैं ऐसे में इनको आराजी की अवाप्ति होने पर मुआवजा राशि प्राप्त करने का पूरा-पूरा अधिकार है। अधिवक्ता प्रार्थी/प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत नजीरें आर.आर.टी. 2017(2) पेज 883 लूनियावास गृह निर्माण सहकारी समिति लि० बनाम् स्टेट ऑफ राजस्थान, आर.आर.टी. 2016(1) पेज 723 रामप्रताप बनाम् कमलाबाई, आर.आर.टी. 2018(1) पेज 175 छीतर एवं अन्य बनाम्

श्रीमती भंवरीदेवी एवं अन्य इस प्रकरण में हूबहू चशपा होती हैं। उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि वादीगण द्वारा यह वाद मंहज प्रतिवादीगण को परेशान करने एवं उनकी मुआवजा राशि रूकवाने के लिये ही प्रस्तुत किया गया है, जिसे अब और लम्बित रखना न्यायोचित नहीं है। यहां हम प्रार्थी/प्रतिवादी के प्रार्थना-पत्र से पूर्ण रूप से सहमत हैं तथा यह स्वीकार योग्य है।

अतः प्रार्थना-पत्र प्रार्थी, अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सिविल प्रकिया संहिता 1908 स्वीकार किया जाता है तथा वादी का वाद संख्या 753/2017 घनश्याम बनाम् द्वारकालाल चलने योग्य नहीं होने से खारिज किया जाता है। प्रार्थना-पत्र निर्णय में शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा वाद तामील तकमील मूल वाद के संलग्न रहे।


उपखण्ड अधिकारी
खानपुर जिला झालावाड़
(राजस्थान)

निर्णय आज दिनांक 23/10/2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


उपखण्ड अधिकारी
खानपुर जिला झालावाड़
(राजस्थान)

